[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]

अधिकारी नही हू कि मैं अधिकार पूर्वक कह सकू कि अगर उन लोगो को नही मिला, तो अनुचित हुआ । किन्तु हमारे क्षेत्र मे कुछ लोगों की चर्चा है जिनके बारे मे जनता सोचती है कि उन को मिलना चाहिए ।

मै एक व्यक्ति को जानता हू । वह एक ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है, जो स्वराज्य पार्टी का लीडर था, जो बहुत ही बडा ट्रेड यूनियन लीडर भी था—वह इलाहाबाद का युवक था । कुछ और व्यक्ति हमारे आस-पास के थे । मेरा ध्यान है कि हमारे रक्षा मत्री इन बातो पर थोडा ध्यान दे कर आवश्यक कार्यवाही करे ।

जैसा कि कई साथियो ने कहा है, हमारे कुछ पडौसी देश हैं, जिन से हमे सदा आक्रमण का भय है और इस लिए हमे सतर्क रहना है । इस हेतु अभी तक हमारी जो शक्ति सबसे अधिक कारगार हुई है, यानी वायुसेना की शक्ति, उस शक्ति मे और वृद्धि करनी चाहिए । इस सम्बन्ध मे सुझाव भी आये हैं ।

MR DEPUTY-SPEAKER The hon Member may continue his speech on the next day.

15.57 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Ninth Schedule)

SHRI C. K CHANDRAPPAN (Tellichery): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India

MR DEPUTY-SPEAKER . The question is

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

The motion was adopted.

SHRI C K. CHANDRAPPAN : I introduce the Bill.

UTILIZATION OF CULTIVABLE RAILWAY LAND BILL*

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अल्मोडा) · उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू "कि रेल पटरी के दोनो ओर की भूमि तथा अन्य रेल भूमि की खेती बाड़ी के लिये उपयोग करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the utilization of land on both sides of railway track and other railway land for agricultural purposes".

The motion was adopted

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : मै विधेयक को पेश करता हू ।

MR. DEPUTY SPEAKER · The next two Bills are standing in the name of Shri Bhogendra Jha But the hon Member is absent

SHRI S M BANERJEE (Kanpur): He has been sent to jail.

15.59 hrs.

FILM INDUSTRY WORKERS BILL

By SHRI S C SAMANTA—*Contd*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri R. S. Pandey on the 14th April, 1972 —

"That the Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry, be taken into consideration"

Shri J M Gowder—absent Shri Bade—Absent.

AN HON MEMBER: Mr. Gowda is here.

16 hrs.

SHRI D B. CHANDRA GOWDA (Chikamagalur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to speak—*(Interruption)*.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28. 4. 72.

MR. DEPUTY SPEAKER: Are you Mr. Gowder? Shri J. M. Gowder was on his legs the other day. What Gowder are you?

SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: I am D. B. Chandra Gowda.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I was calling Mr. J. M. Gowder. Anyway, you can speak.

SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Mr. Deputy Speaker, Sir, on this Bill—Film Industry Workers Bill—I would like to speak in Kannada. (*Interruption*).

AN HON. MEMBER: The translation is not coming.

SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Sir, I would like to congratulate the hon. Member who brought this Bill which certainly relates to more than 10 lakhs of workers working in this industry.

16.01 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

It is said that the Industrial Disputes Act or the Minimum Wages Act or the benefits of gratuity are not applicable to these workers. It is certainly regrettable to note that these unfortunate workers could not be brought within the purview of the laws laid down in the country. But, at the same time, this particular aspect is to be viewed in consultation with and in the light of the actual film producers, film exhibitors and film distributors. I would like to draw your attention to the fact that we have about 57 studios in all, in the whole country. Particularly the producers in this country do not get proper aid on the attention, they should have got in a democratic country. I would like to make a mention here that the only source of financial help that the producers could look to is from the Film Finance Corporation of India which, with its capital of Rs. 1 crore and a working capital of Rs. 50 lakhs, could not cater to the entire needs of the film producers. Therefore, these producers must depend and completely depend upon the distributors mainly, and to same extent the exhibitors also. This is a critical situation. The share that the producers get out of the total income comes to about 5%. About 95 per cent goes to the exhibitor, the distributor and as revenue to the Government. Unless we try to improve the financial position of the producers, we cannot think of giving some relief to the workers. I recall a famous proverb: as is the master, so is the servant. If the master is a bankrupt, he cannot think of giving a substantial dividend to the servant.

This Bill has been brought forward in the interest of more than ten lakhs of workers. I feel that it is not comprehensive enough. The Government should take this Bill into consideration; in fact it should have been brought as a Government Bill rather than a private Members' Bill. Government earns a revenue of more than Rs. 150 crores from this industry. The industry, especially the producers should get a loan at an easy rate of interest so that they are not dependent on exhibitors or distributors alone. The purpose of the Bill is to give some relief to the ill-fed workers; there are more than ten lakhs of them in this country. The purpose of the Bill will not be achieved unless the production machinery is properly looked after. Therefore, while congratulating the hon. Member who has brought forward this Bill, I would request the Government to take it up as a Government Bill and bring forward a comprehensive measure to benefit both the worker as well as the producer.

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : सभापति महोदय, जरूरत तो इस बिल की बहुत पहले थी और मैं समझता हूं कि लेबर मिनिस्टरी ने इस तरफ पहले ध्यान नहीं दिया जिस की वजह से इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर जो हैं वह दिन प्रति दिन और परेशान हो रहे हैं। मैं श्री आर० एस० पांडे को यह बिल लाने के लिए मुबारकबाद देता हूं। तकरीबन 25 करोड़ रुपया रोजाना इस इंडस्ट्री का बिजनेस है और 10 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट्स की तरफ देखते हैं, उनको इस बिल की, मिनिमम वेजेज ऐक्ट की या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की कोई परवाह या कोई जरूरत नहीं है। उनको यह प्राबलम टच नहीं करती दिलीप कुमार को, राजकपूर को, आशा पारेख को या राजकुमार को ..(व्यवधान)...नरगिस को भी। लेकिन वे गरीब वर्कर्स जो छोटे कैमरा मैन हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, डान्सर्ज हैं, पेन्टर्स हैं,

[श्री सतपाल कपूर]

ड्राइवर्स हैं, जो इस इण्डस्ट्री मे काम करते है, इनके अलावा जो सिनेमा मे काम करने वाले वर्कर्स है, जैसे गेट-कीपर्स, फिल्म चलाने वाले लोग, इन तमाम की जिन्दगी से इस बिल का गहरा ताल्लुक है। मै यह तो नही कहता कि यह बिल बिलकुल मुकम्मिल है, इसमे कई खामिया हो सकती है, लेकिन

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनदगाव) : यह मिनिस्ट्री ही मुकम्मिल नही है।

श्री सतपाल कपूर : मिनिस्ट्री तो मुकम्मिल है, लेकिन इस मिनिस्ट्री ने इस तरफ ध्यान नही दिया। इसमे मिनिस्टर हे, डिप्टी मिनिस्टर है, लेबर सैक्रेटरी है, तीन-चार ज्वाइन्ट सैक्रेटरी है, तीन-चार डिप्टी सैक्रेटरी है, 5 अण्डर सैक्रेटरी है, कान्सीलियेशन आफिसर है, गर्जेकि पूरा स्टाफ है, लेकिन इस तरफ ध्यान नही दिया गया।

मै चाहता हू कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय या मिनिस्टर साहब इस बात का वायदा करें कि वह इसकी तरफ अब पूरा ध्यान देंगे और बहुत जल्दी हाउस के अन्दर एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लायेगे, जिसमे वे तमाम बाते--जो इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट मे आती है, उनकी तमाम सहूलियतो के बारे मे, मिनिमम वेजेज के बारे मे और उन तमाम चीजो के बारे मे जिन से इस इण्डस्ट्री का वर्कर आज तक सफर करता रहा है, नुक्सान उठा चुका है, ग्रेचुइटी, प्राविडेन्ट फण्ड, इन तमाम चीजो के लिये प्रोवीजन होगा।

जहा तक इस बिल का ताल्लुक है, मैने इसकी जितनी क्लाजेज पढी है, मुझे तो ये काफी मुकम्मिल और दुरुस्त नजर आती है। मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नही आई, जिस को कहा जाय कि वह वर्कर्स के इन्टरेस्ट को पूरा नहीं करती। इस तरफ पहले ध्यान देना चाहिये था, जो नही दिया जा सका, लेकिन आज भी अगर एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आया है और अगर कोई कमी है तो उसको कन्सीडर कर सकते है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : सभापति महोदय, चल-चित्र उद्योग मे रोजगार और सेवा-नियोजन (एम्पलायमेंट) की जो हालत है, वह सिर्फ दर्दनाक ही नही है, बल्कि एक बहुत भयकर और गम्भीर, खतरनाक परिस्थिति है और अगर अब हमने उसको सुधारने के लिये बिना विलम्ब किये कोई व्यापक शल्य-क्रिया नही की तो यह निश्चित मान लीजिये कि इस रोजगार मे जो 10 लाख आदमी काम करते है और जिस तरह से दिन-प्रति-दिन उन की हालत बिगड़ती जा रही है, एक रोज वह आयेगा कि किसी दिन अगर खूनी क्रान्ति शुरू होगी, मजदूरो का अपने मुल्क के खिलाफ, तो ये फिल्म इण्डस्ट्री के लोग उसमे सबसे आगे होगे। इस इण्डस्ट्री मे जो कैजुअल वर्कर्स काम करते है, जो अनियमित रोजगार के लोग काम करते है, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, मान्यवर, कभी आप उनके शोषण को देखे तो आप इस नतीजे पर पहुचेगे कि जिस तरह से इस समस्या को नजरअन्दाज किया गया, वह एक अक्षम्य गुनाह है।

मै इस बात को मानता हू कि पाडे जी का बिल शायद मुकम्मिल नही है, काम्प्रीहैन्सिव नही है, लेकिन यह वकील नहीं है, जितना उन से बन पाया है, उतना उन्होने किया है, अगर इसको पारित कर ले, स्वीकार कर लें, तो उस से औद्योगिक विधि शास्त्र, इण्डस्ट्रीयल जूरिसप्रूडेन्स के क्षेत्र मे, मालिक और मजदूरों के सम्बन्धो में कोई बड़ी भारी क्रान्ति आने वाली नही है। लेकिन मैं आशा करता हू कि इस उद्योग मे रोजगार के सम्बन्ध से श्रम मत्रालय अफीम का गोला खा कर कुम्भकरण की निद्रा मे सोया हुआ था, उसको झझोड़ने की दिशा में यह बिल काम करेगा। इस लिये पाण्डे जी ने जो कहा है, वह बड़ी सराहनीय बात है, प्रशसा की बात है, इस का हम लोग स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं।

मान्यवर, इस उद्योग में रोजगार के तीन वर्ग हैं—पहला वर्ग तो वह है जो कलाकारों से सम्बन्ध रखता है, जिन्हें फ्री-लान्सर-आर्टिस्ट कहा जाता है। इसमें आप के बड़े बड़े नायक और नायिकायें आती हैं, जिन के कुछ नाम अभी लिये गये। पाण्डे जी हमारी संसद् में आ गये, अगर संसद में न आते तो फिल्म क्षेत्र में रहते तथा नायकों की पंक्ति में बैठे होते .....

श्री सतपाल कपूर : यह तो अभी भी अभिनेता हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इनके अलावा और लोग हैं जैसे संगीत निर्देशक, प्ले-बैक सिंगर, इन लोगों की मेरे ख्याल से बड़ी ग्लैमरस लाइफ है और यही लोग नजर के सामने आते हैं, जिनको देखकर हम यह समझते है कि यह उद्योग बड़ा खुशहाल होगा। अगर इस तबके को छोड़ दें, जो फ्री-लान्सर तबका है और जैसे प्रोड्यूसर लोग समझते हैं कि कला के नाम पर चाहे जो चीज बना दे, नंगी और अश्लील तस्वीरें, पैसा कमाने के लिये, बाक्स-आफिस के लक्ष्य को सामने रखते हुए चाहे जैसी तस्वीर बना दें, लोगों को तो देखना ही होगा क्योंकि मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है, उसी तरह से हमारे कलाकार, ये फ्री-लान्सर लोग समझते हैं, न इनके जीवन में किसी अनुशासन की जरूरत है, न ही कोई नैतिक मूल्य इन पर लागू होता है। बहरहाल इसके नुकसान के मुतालिक आंसू बहाने की जरूरत नहीं है।

दूसरा वर्ग यह है जो टैक्नीशियन्ज कहलाते हैं, उनमें कैमरा-मैन हैं, साउण्ड रिकार्डर्स हैं, इन लोगों की जो स्थिति है, जो एम्पलायमेंट कण्डीशन्ज हैं, उसको भी किसी हद तक समाधानकारक माना जा सकता है। इनमें बहुत से लोग ठेके पर काम करते हैं, इसलिये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है—मेरे ख्याल से 10 लाख में से 8 लाख लोग इस वर्ग में आ जायेंगे, जो अनियमित मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, इस श्रेणी के लोगों पर जो गुजरती है, उसको आज तक इस मन्त्रालय ने नजर-अन्दाज किया है। आप इस विधेयक को कुबूल करें या न करें लेकिन इतना आश्वासन जरूर दें कि इस इण्डस्ट्री में जो शोषण होता है, जिस तरीके से युवक और युवतियों को एक्स्ट्रा के रूप में कान्ट्रैक्टर्ज लाते हैं, जिस तरह से उनको पेमेंट किया जाता है, जिस तरह से उनको चलाया जाता है, उसकी तरफ आप जरूर ध्यान देंगे। यदि वहां पर देखा जाय तो, सभापति महोदय, मानव प्रतिष्ठा और मानव-गौरव को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी एक्जीबीशन हम वहां देख सकते है, उसको देख रहे हैं और शान्ति से कुछ नही कर पा रहे हैं। बम्बई की यह बात मशहूर है, पाण्डेय जी इस बात की गवाही देंगे, वहां पर जो छटा हुआ गुण्डा होता है, जिसे दादा कहते हैं, जो दादागीरी के काम में बहैसियत एक गुण्डे के रेपूटेशन हासिल कर लेता है, वह किसी दूसरे धन्धे में नहीं जाता फिल्म की तरफ अपना मुहं कर लेता है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक्सप्लायटेशन का सबसे ज्यादा स्कोप होता है, जरूरत से ज्यादा फायदा होता है, ऐसा आदमी कांट्रैक्टर की हैसियत से इन एक्सट्राज को लेकर आता है और जिस तरह से किसी जमाने में गुलामों की ट्रैड हुआ करती थी, उस तरह का ट्रीटमेंट इन लोगों को दिया जाता है। अगर इस बात का कोई प्रमाण चाहिये तो मन्त्री महोदय कभी मेरे साथ बम्बई चलें-इन-कागनिटो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और चल कर देख लें कि यह बात सच है या नहीं है।

जैसा मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा—यह एक बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। हमारे यहां जनमत बनाने के लिये इस इण्डस्ट्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे यूथ के ऊपर भी फिल्मों का एक जबर्दस्त प्रभाव रहता है। जिस तरीके की आजकल फिल्में आ रही हैं उनमें कला और संस्कृति का कोई नामोनिशान नहीं होता। हर कोई एक फार्मूला बनाकर चलता है, पुरानी घिसी हुई थीम्स को लेकर चलता है, किसी न

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे]

किसी सूरत से कुछ गाने रख दिए, कुछ डान्स रख दिए और कुछ अश्लीलता रख दी और इस तरह से फिल्म का एन्ड हो जाता हैं। प्रोड्यूसर्स इस तरीके की फिल्में बनाकर हमारे यहां के वातावरण को आजकल दूषित कर रहे हैं और उसको हम नजरन्दाज कर रहे हैं। यही एक इण्डस्ट्री है जिसको अगर हम नेशनलाइज कर लें तो हमारा बेशुमार फायदा हो सकता है। हमारे जो सामाजिक लक्ष्य हैं उन को प्राप्त करने के लिए इण्डस्ट्री को हम नेशनलाइज करें तो हमे बहुत ज्यादा सुविधा हो सकती है। यही कह कर मैं एक दफा फिर पांडे जी की तारीफ करना चाहता हूं कि वे इस बिल को यहां पर लाए।

SHRI G VISWANATHAN (Wandiwash): Who will be the actors and actresses if you nationalise?

SHRI N K P. SALVE: If we nationalise, there is going to be no dearth of actors and actresses and my learned friend will do well to remember that his party is full of actors and actresses even on the political stage.

SHRI G. VISWANATHAN: What about your ministers?

SHRI N. K. P. SALVE: Many of my ministers have made you dance on the stage also. In that view of the matter I assure you that you need entertain no apprehension on the score that we will be deficient in finding out artistes.

SHRI G. VISWANATHAN: We know that you will only talk and will not do.

SHRI N. K. P. SALVE: Yes, that is my grievance. We are talking of achieving our social and economic objectives and this is one medium, a very effective medium, of building up public opinion. It is very essential that we do consider very seriously this proposal of nationalising this industry so that this effective medium comes into the hands of the Government.

*SHRI G. VISWANATHAN: Hon. Mr. Chairman, Sir, I am happy to participate in the discussion on the Film Industry Workers Bill, introduced by my hon. friend, Shri S. C. Samanta and moved by Shri Ramsahai Pandey for consideration.

Sir, you know that the film industry is one of the oldest industries in our country and a bill of this nature seeking to provide mechinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the film industry should have been brought before this House many years earlier. When we think of the film industry, immediately we begin to talk about the actors, actresses, producers and directors. Whenever any discussion about film industry had taken place in this House, we had all waxed eloquent about the financial problems faced by the producers. When the Report of the Khosla Committee came up for discussion in this House, the Members expressed their view-points as to whether kissing in films should be permitted or not. Similarly, we had a heated discussion as to whether nudity in films should be allowed or not. But, so far nobody has worried about the lakhs of workers in the film industry. The concerned Ministry also has not cared to look into the conditions of these workers. The Members of this House also have not shown any concern about the film industry workers. It is the good fortune of this House that this Bill has been introduced by Shri Samanta.

Sir, India occupies the second position in the world in regard to the number of films produced. Every year we are producing 400 films a year. Our films are exhibited in many countries of the world. In our own country we have about 10000 theatres. Three lakhs of workers are employed in the film industry in its various aspects of activities. When we witness a film, we do not even for a moment realise the hard labour put in by the workers in the production of that film and naturally we have not come to realise the hardships and the harassing conditions under which lakhs of workers are toiling in the film industry. I would expect the hon. Minister to inform this House what constructive steps have been taken by the Government to ameliorate the conditions of work and to alleviate the distress of lakhs of workers in the film industry. These workers are denied and deprived of even the basic amenities of life.

Sir, there may be many posh studios in metropolitan cities like Bombay, Calcutta or

*The original speech was delivered in Tamil.

Madras. But these studios are engaged in unceasing activities because of these workers. Apart from these, in every nook and corner of our country, in remote villages, there are theatres in which workers are employed. I would like to know what facilities have been given to them. As my hon. friend, Shri Salve, who preceded me, pointed out, these workers have no statutory support. They have no security of job. They are engaged at will and are discharged at whim of those manning this industry.

This Bill seeks to secure statutory sanction for providing minimum amenities such as leave, shift system, rest rooms, canteens, first-aid, basic minimum wages and improvement in working conditions. As provided for in this Bill, the provisions of the Industrial Disputes Act should be made applicable to these workers. This is an essential prerequisite if we want to improve their lot.

Even at the cost of repetition, I would demand that these workers in the film industry should be given the minimum wage and the benefits of gratuity should also be assured to them. Unlike other sections of industrial workers who have fixed working hours with maximum 8 hours of duty, the film industry workers are always to be at the mercy of producers, directors, studio and theatre owners. They have also to dance to the turn of actors and actresses who get Rs 10 lakhs to Rs. 15 lakhs a film. They have to work hours together continuously without a break for their livelihood. There is no day or night for them so far as their working hours are concerned. Their working hours must be statutorily regulated. It is said that only the agriculturists have no holiday in our country. But, we are doing injustice if we do not remember the fact that the film industry workers also do not have any holidays. Only when the actor or the actress feigns sickness or really falls ill or when the studio is closed due to death of someone high in the film industry, they get a holiday. It is high time that the Government should formulate legal provisions for giving them compulsorily holidays.

It is generally said that black money predominates the film industry. It is universally believed that the actor or the actress gives receipt for receiving only a lakh of rupees, while he or she is paid Rs. 10 lakhs or Rs. 15 lakhs. It is a paradox that in such set up, there is also a section of people known as 'extras' who are given just the lunch or dinner and who get Rs. 2 as their daily wage. What have we done for improving their lot?

Though crores of rupees have been sunk in this industry, the producers are oftentimes faced with financial stringency and they take recourse to collecting in advance from the distributors to the extent of 60% or 80% of their requirement. By advertising the star-cast of an intended film, mentioning the name of a top hero and a top heroine, they solicit the financial favour of the distributors. I am not finding fault with the existing system. But I would like to urge upon the hon. Minister that in such an environment the Government should formulate and implement a definite policy for the welfare of lakhs of workers in the film industry.

I do not plead that this Bill as it is should be accepted by the Government. There may be the need for amending certain provisions or for adding some other provisions in this Bill. It will be proving the good intentions of the Government so far as the film industry workers are concerned, if the Government accept the Bill in principle and appreciate the objectives of the Bill.

I would appeal to the hon. Minister that by the end of this year the Government should ensure the enactment of a comprehensive bill for the welfare of film industry workers. We have slumbered long enough. Having woken up, let us not doze but act energetically, effectively, and expeditiously.

With these words, I welcome this Bill.

SHRI N. K. SANGHI (Jalore): Mr. Chairman, Sir I am very glad and so are the hon. Members of this House that Shri R. S. Pandey who is our trusted colleague has piloted this Film Industry Workers Bill, 1972. A lot more has been said in decrying the films in the background of this Bill and, I think, it is proper that the records are put straight.

Today, the film industry employ as much as Rs. 150 crores total investment. There is an annual earning from the industry by screening the films to the tune of approximately Rs. 160 crores. Out of this, Rs. 70 crores go to the State Governments by way of entertainment tax. Not only this. The industry has more than 2 lakh workers and not 10 lakh workers as has been said previously. This industry has been producing films for a number of years.

[Shri N K Sanghi]

Who has really failed us today? We talk of black-money, we talk of unethical practices, we talk of star-system, we talk of extra-suppliers' system and all that I can assure you, and, I am sure everyone will join me, that we are not in favour of anyone of these practices black money unethical practices and all that They have got to be rooted out This is something that we have to do in this House We have really to see if somebody has failed, why all these practices have persisted in this way all these years It is a matter of serious concern to all of us here We have to look into it Today we cannot deny the fact that films have a great social importance in this country Today they have become the only source of entertainment to the millions of toiling people in this country We cannot deny that films should not be there They have made a very good progress Today the film industry in India is the fifth largest industry It is today the largest film producing concern in the world Japan and America which used to be the fore runners have today gone backward of India s production in 1971

In this background we have to see this Many times Government comes up with various legislations In 1951, Patil Enquiry Committee was set up They gave certain recommendations The whol thing was gone into minutely but the whole report has been shelved during the last 21 years No action was taken Then we heard in this House that a Film Council would be instituted and that was somewhere in 1969 Since then it was being said that it was coming and coming I do not know when it is coming Lately, this year, we heard that Films Council would be set up in an advisory capacity and not as a statutory body That also, I do not know how it is coming—what is the framework, what will be the terms of reference, etc These are important when Government takes up the matter When they make a pronouncement on the floor of the House that they will do something we expect them to take some decision quickly

On the subject of Film Workers' Bill, I would like to draw attention to a circular which has been issued by the Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation on 23 January 1970 It gives a resume of what happened on Film Workers' Bill. It says :

> " a draft scheme of legislation to regulate employment in Film Industry was Placed before the 24th Session of the Standing Labour Committee held in February, 1966 "

It further says

> 'It was agreed that a tripartite committee should be set up to consider the draft scheme and make suitable recommendations in this regard The proposed Committee should consist of one representative each from the Central organisations of workers and employers and representatives of Ministries of Information and Broadcasting and Labour, Employment and Rehabilitation and of the State Governments of Maharashtra, West Bengal, Madras and Andhra Pradesh '

It further says

> In pursuance of the above recommendation a tripartite committee of 14 members was set up in this Ministry s letter No LWI—(I)—6/13/66 dated 23rd November 1966 The Committee was required to examine the draft scheme of legislation and to make further recommendations in this regard '

It further says

> "The Committee submitted its report in September 1968"

This Committee was headed by Shri N N Chatterjee the then Joint Secretary in the Ministry of Labour and Rehabilitation It had all the members and it went to Bombay, Madras, Hyderabad, Calcutta and other places and also had a sitting in Delhi A lot of evidence was taken from stars, writers and artistes and various people who have been engaged—representatives of employees' unions and all that After this report was submitted, it is said :

> "It is proposed to place the Report of the Tripartite Committee which examined the draft scheme of legislation before the next meeting of the Standing Labour Committee"

This report was endorsed by the 27th Session of the Standing Labour Committee of the Indian Labour Council That was in 1969. This is the state of the Film Works' Bill that has been discussed for the last more than five

years. It had a tripartite committee ; recommendations were formulated ; legislation was drafted ; and it was endorsed by the Indian Labour Council. And this is the state of affairs. In 1969 something was discussed and finalised. May I know from the Government what has happened all these years ? Why have they not been able to bring forward a legislation ? What is the idea ? A committee like this takes years and years for formulation. And when it is finalised, then also it takes years and years. It goes into the archives. Naturally there is so much of heart—burning so much of agitation. Labour laws do not work. I would humbly point out that it is not that the film industry does not have a legislation. For example, studios, etc. are governed by the various legislations that we have. We have the Factories Act, the Payment of Minimum Wages Act, the Workmen's Compensation Act and the Industrial Disputes Act and Employees State Insurance and Provident Fund, Act etc. All this legislation applies to the laboratories as well as the studios. We have the Minimum Wages Act all these years which is applicable to the cinemas wherever they are running and some of the Shops Establishments Act and the Minimum Wages Act apply to the exhibitors. Similarly, the Shops & Establishments Act is applicable to the distributors.

To-day, whose problem is it? Certainly, it is a very big problem in the film industry. Things are not being looked into from a particular angle. The main problem is about the writers, the lyric writers and script writers who do not come under the definition of 'workmen'. 'Workers', as you very well know, are those who are manual or non-manual, skilled or unskilled. That is the definition of a 'Worker'. Unfortunately, artistes, writers, lyric-writers and script-writers, all these people do not come under the definition of 'workers', as the Solicitors and Lawyers do. You are yourself an eminent lawyer. You know better. They do not come under the definition of 'worker'. Similarly, teachers do not come under the definition of 'worker'. It is for this reason that these casual artistes, these casual lyric-writers and music-composers should be brought under a proper legislation.

Moreover, we have to understand what sort of labour-management relations is there in the film industry. They are always drafted on temporary employment. They work for ten days, 15 days or 30 days or for a season. For this reason, there ought to be some comprehensive legislation for these people who work for part time and who do not have the advantages of the Bonus Act, who do not have the advantage of the Employees State Insurance and other socially beneficial legislation. Of course, E. S. I. premium is deducted when they are working for a week or so but they do not get the ESI card because they are not permanent employees. They have to pay something for which they are not able to take advantage of. Then, what happens?

There is a hazard also in this industry. When films are being produced, there is a riding shot. There may be a fire shot. There may be battle scenes. They are very hazardous operations. When you are shooting these films, sometimes, it may result in accidents and some people may get killed. There is no way to cover such risks. The Insurance company won't give you the Group Insurance Scheme and where they do not give group insurance, you cannot take out a policy also. I can illustrate for example if there was an accident in which ten people were killed. Sir, to-day workers compensation for death is Rs. 14,000. If 10 persons are killed and compensation is paid at Rs. 14,000 per worker the producer will have to close and go to lock, stock and barrel. This is the position of the risk involved. We have to do something and instead of bringing some sort of temporary relief to these workers, we have to think about some comprehensive legislation. But the question is that since the legislation has already been gone into and evidence has been taken for it, all the Employees' Unions are agitating to the Govenment for this legislation saying 'Whatever you have already finalised, please bring it on the floor of the House' so that we poor people, can take advantage of it.' This is the malady in which we are to-day. To-day, when we discuss things everything has gone wrong. Whatever little we have to do is not being done. This is the blame of the film industry that would lie on the shoulders of the Members of Parliament here and we have to do some thing.

Film is an important mass medium. It has helped in making Hindustan the *lingua franca* of the country from Kashmir to Cape Comorin and from Bengal to Rajasthan and people can to-day understand, talk and appreciate Hindustani language. This is what the films have done for us. They have also brought about a sort of social transformation by removing regional and caste barriers, by making people know their problems. To-day workers in the Film Industry are

[Shri N. K. Sanghi]

marching shoulder to shoulder in the progress and prosperity of the country I speak here, Sir, for 90% of the people who are engaged in the film industry. To-day, they have no subsistence. They are below subsistence. It is for these workers I humbly request the Government to do something and see that a proper legislation is brought forward and what they have got should be piloted in the House, and if they want a proper codification, let it go immediately to a Select Committee where they should get it finalised with a time-bound programme and a proper legislation should be brought forward to these casual workers who to-day do not get their due rights.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं माननीय राम सहाय पाडे जी को धन्यवाद देता हू कि चलचित्र मे काम करने वाले हजारों लोगों के दुख को उन्होने समझा है। वह उनको बधाई देगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बिचौलिये है इनका जब तक नाश नही होता है तब तक देश में से शोषण नही मिटेगा, और जो हम बात करते है कि एक ऐसा समाज बनाना चाहते है जिसमें कोई शोषण करने वाला न हो, वह बात भी तभी पूरी होगी जब बिचौलियों को हर क्षेत्र मे से निकाला जायगा।

साघी साहब ने जो कहा ठीक ही कहा कि छोटे-छोटे गावो से जो कलाकार आते हैं, और जो साहित्यिक है, जो इस काम को करना चाहते है, उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है इस शोषण से बचाने के लिये इस कानून की जरूरत है। मेरे खयाल से हमारे श्रम मन्त्री इस बात से इन्कार नही करेंगे। आज तमाम देश इस तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, आज जनता आप से मांग करती है कि हमको इस तरह का कानून चाहिये। आज बिचौलियो के कारण क्या होना है कि वह हम लोगो के साथ गद्दारी करते हैं, इन्सानियत का खून करते हैं। जो बेबस लोग हैं उनको वह अपने जुल्मो का निशाना बना रहे हैं। मैंने चेम्बर और बम्बई मे जा कर देखा है, और लोग हमसे बतलाते है, कि जो लोग मजबूर होकर वहां जाते है उनका शोषण किया जाता है। वह अपनी जिन्दगी ठीक से बसर नही कर सकते। मैंने देखा है कि आज देश मे जो तमाम मन्दिर, मस्जिद और गिर्जाघर है, उनमें कोई जाना भी पसन्द नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं सिनेमा चल रहा हो तो वहा सभी लोग जाना चाहते हैं। मैं समझता हू कि कई जगहों पर जहा मन्दिर और मस्जिद बने हुए है अगर उन स्थानों में साथ साथ सिनेमा भी चला दिये जायें तो मन्दिरों और मस्जिदों की भी थोडी बहुत कद्र हो जायेगी क्योंकि लोग कम से कम वहा जायेगे तो।

अभी श्री माल्वे बोल रहे थे। मुझे मालूम हो रहा था कि वह भी कलाकार है। वह भी ऐसी भाषा बोल रहे थे कि सिनेमा लोगों को नई जिन्दगी देने वाला है और जिन बूढ़ों मे कोई नयापन न आना हो, उनको पिक्चर मे ले जाना चाहिये। सिनेमा ने दुनिया में एक हलचल मचा दी, देश मे जो दीवारे है उनको उसने तोड़ दिया है। जातिवाद और सम्प्रदायवाद की दीवारों को तोड़ कर एक नया जीवन देने के लिये, चाहे वह युवकों में हो, चाहे और लोगों में हो यह चलचित्र सहायक होते हैं। चलचित्र देश को आगे ले चलता है और देश को गौरव होना चाहिये कि हमारे यहां यह इडस्ट्री बडी अच्छी तरह से विकसित हो रही है।

माननीय सदस्यों ने कुछ आलोचना की कि चलचित्रों में बड़ी गन्दगी है, बड़ी अश्लीलता है। यह तो देखने वालों की नजरों पर कभी-कभी निर्भर करता है। अगर हम इसको किसी और रूप में देख लें तब भी काम चल सकता है, लेकिन दरअसल चलचित्रों में कुछ आइडियाज होते है। (व्यवधान) आप की अवस्था चलचित्रों लायक नहीं हैं, आपके लिये तो कोई आश्रम चाहिये, स्वर्गाश्रम हो या गीताश्रम हो, आप उसके उपयुक्त हैं, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिये उसमें बहुत कुछ है। चलचित्रों ने देश के अन्दर एक क्रान्ति पैदा की

है इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन जो क्रान्ति लाने वाले हैं उनकी ओर कोई नहीं देखता है। सब लोग दीपक की रोशनी को देखते हैं, लेकिन दीपक जलाता कौन है उसको कोई नहीं पहचानता। सब लोग दीपक की लौ को देखते हैं, लेकिन दीपक को कोई नहीं देखता। जो कलाकार हैं, जो इस रोशनी को लाने वाले हैं, देश को नयापन देना चाहते हैं, उनका शोषण हो यह उचित नहीं है। श्री बाल गोविन्द वर्मा मिनिस्टर हैं। वह भी इससे ऐग्री करते होंगे कि उन लोगों का शोषण न हो। वह समझते होंगे कि जो गलत काम आज इस उद्योग में हो रहे हैं वह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री पांडे एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, उनके पास बैठने वाले श्री माल्वे भी वैसे ही हैं। इसलिये मैंने सोचा कि उनके स्वर में मेरा स्वर भी मिलना चाहिये क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल इतना जरूरी है जिसके बारे में लेबर मिनिस्टर को अपनी मर्यादाओं में रहते हुए विचार करना चाहिये। उनको टाइम बाउंड समय बतलाना चाहिये। **ऐज सून ऐज पासिबिल** वाली बात ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिये कि इतने समय में वह यह कानून लाने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि आज देश में हजारों क्या लाखों कलाकार जो हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिये। उनकी शक्ति, उनके मन, उनके दिल, उनके संस्कार का अधिक से अधिक विकास होना चाहिये। आप कलाकारों को जितने अच्छे काम के अवसर देंगे उतना ही उनका विकास होगा।

मैं समझता हूं कि जो बिल लाया गया है वह बहुत आवश्यक है। यहां पर वादविवाद में सारी बातें कही जा चुकी हैं, इसलिये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी कानून का रूप दिया जाये।

श्री बसंत साठे (अकोला) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री पांडे द्वारा रक्खे गये बिल की तहे दिल से ताईद करता हूं, साथ ही आपकी भी, जब आपने बहुत अच्छे शब्दों में, पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन किया और खास कर यह विचार रक्खा कि जो तमाम चलचित्र उद्योग है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

मैं तो समझता हूं कि किसी भी पिछड़े हुए देश में, जिसको तरक्की करनी हो, समाजवादी समाज व्यवस्था लानी हो, यह जो चलचित्र उद्योग का माध्यम है वह शिक्षा का, लोक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। एक माध्यम है दूर वाणी का, दूसरा माध्यम जो मास कम्यूनिकेशन का है यह चलचित्र है। चलचित्र एक ऐसा माध्यम है जो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिये अपना स्थान रखता है और प्रभावित करता है। मैं यह मानता हूं कि यदि अपने देश में नई पीढ़ी को कुछ अच्छे संस्कार देने हैं तो उसके लिये इस माध्यम का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है।

दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तरफ, कामगरों की तरफ, कलाकारों की तरफ, हमारा ध्यान नहीं गया। औद्योगिक क्षेत्र में कानून की काफी तरक्की हुई है। जीवन के तमाम अंगों को औद्योगिक कानून ने स्पर्श किया है, लेकिन जैसा आपने भी कहा, मेरे मित्र श्री सांघी ने भी कहा, क्या वजह है कि लाखों लोग जिस उद्योग में काम करते हैं उस उद्योग को हमारे कानून, मजदूर कानून, औद्योगिक विवाद सम्बन्धी जो कानून हैं वह स्पर्श न करें? जो सिनेमागृह हैं उनमें जो लोग दिन रात काम करते हैं उनको संरक्षण क्यों नहीं मिलता? यहां कह दिया जाता है कि राज्यों के कानून होंगे, शाप इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट सरीखे, उनमें संरक्षण मिल सकता है। लेकिन यह क्यों जरूरी है? हमारा औद्योगिक विवाद कानून बहुत काम्प्रिहेन्सिव है, लेकिन वह भी अभी तक जितने लोग हैं उन पर लागू नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभी ऐसा मानते हैं कि यह उद्योग ऐसा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऐक्टर्स हैं, ऐक्ट्रेसेज हैं और

[श्री वसन्त साठे]

प्रोड्यूसर्स है, जो करोडो रुपये कमाते है, काला रुपया कमाते हैं और बडे मजे मे रहते हैं, इसलिये इस तरफ देखने की कोई जरूरत नही। देश के दो लाख लोग, या दस लाख लोग करोडपति हैं और काले पैसे मे मजे कर रहे है, ऐसी एक धारणा हमारी बन गई है, नही तो मैं कोई ऐसा कारण नही देखता कि कमेटी बैठी, उसने रिपोर्ट दी और 1966 से लेकर आज तक हम इस विषय की ओर जरा भी गम्भीरता से न देखते ।

आपको मालूम नही कि इन कलाकारो मे कौन से कलाकार क्या काम करते हैं। जो एक्स्ट्राज होते है दिन भर उनको लाकर बिठाया जाता है, कब उनका नम्बर आयेगा पता नही। रोज चक्कर लगाते है और हजारो की तादाद मे स्टूडियोज मे घटो बैठे रहते है। रात मे दिन मे कब उनके लिये काम आयेगा यह आप बता नही सकते। आपको पता है कि जो लोग स्टूडियोज मे काम करते है वह बडी तकलीफ मे रहते है। उनके वेतन का कोई ठिकाना नही, उनको पता नही लग सकता कि कब वे काम करेगे और कब उनको पैसा दिया जायेगा। उनका वेतन कोई नही, फिर उसमे एक भयानक अनैतिकता इस क्षेत्र मे आती है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिये। परसो आपने सुना कि उडीसा की लडकियों के साथ क्या हुआ। मैं आपसे बतला रहा हू कि बम्बई मे गरीब घर की लडकिया ही नही, अच्छे अच्छे घरो की लडकिया इस आशा से आती है कि वह अच्छी कलाकार हो जायेगी। वह एक्स्ट्राज के बाजार मे चली जाती है। उनका कितना दुरुपयोग किया जाता है और सामाजिक दृष्टि मे उनका कितना अध पतन हो जाता है, आप जरा इस तरफ भी ध्यान दीजिये। सरकार कानून बना कर यह व्यवस्था करे कि जिस किसी को काम के लिए बुलाया जाये, चाहे वह एक्स्ट्रा हो और चाहे कोई और काम करने वाला, उसको उचित वेतन दिया जाये, जैसे कि टेक्सटाइल इडस्ट्री मे बदली कामगरों को दिया जाता है। तब वे अपने आपको बेचने की बात नही सोचेगे। आज उनकी जो हालत है, सरकार को उसे मानवता, महानुभूति, अनुकम्पा, और मै तो यहा तक कहूगा कि स्त्री-दाक्षिण्य की भावना से देखना होगा।

माननीय सदस्य, श्री पाडे, ने यह बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अक्सर हम देखते है कि जब कोई प्राइवेट मेम्बर्ज का बिल आता है, तो मत्री महोदय कह देते है कि हम भी इस बारे मे विचार कर रहे है, वगैरह।

श्री राम सहाय पांडे उन्होने कहा है कि वह इसको स्वीकार कर लेगे।

श्री वसंत साठे· अगर वह इसको स्वीकार कर लेगे, तो सोने म सुहागा है। मै श्री पाडे से कहूगा कि वह इस बिल को विदड्रा न करे। वह नेता है—वह अभिनेता है। आप भी अभिनेता है। मै तो अभी अभी आया हू, अभिनेता नही बना हू। मत्री महोदय यह ठोस एसोरेंस दे कि वह जल्द से जल्द ऐसा कानून हाउस मे लायेगे। कम से कम औद्योगिक विवाद कायदे मे यह छोटा सा सशोधन कर दिया जाये कि वह फिल्म इडस्ट्री को भी कवर करेगा। इस वक्त इतना कर दिया जाये। पूरा बिल बाद मे लाया जा सकता है। डेफिनीशन आफ इडस्ट्री मे इसको इनक्लूड कर दिया जाये। आज का सारा सवाल इससे हल हो जायेगा।

मै आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे मौका दिया।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA) : Sir, a very lively debate has taken place on this Bill which has been introduced by Shri Samanta, and I am really grateful to the hon. Members for expressing concern over the plight of the workers in the film industry. Shri Pandey, while moving this Bill, mentioned that the Industrial Disputes Act is not applicable to the workers in the film industry

So also, Shri Subodh Hansda said the other day that the Minimum Wages Act is not applicable to them. The other Members who have spoken have also mentioned the deplorable conditions under which these workers are working. You Sir, have also expressed your fear in so far as you have said that casual workers are employed through middlemen and they are very much exploited. We also know that most of the workers in this industry are employed through middlemen ; that the recruitment of workers is beset with several evils ; that favouritism and nepotism are rampant and the workers are exploited in several ways. Indeed, there is actually no security of service. The rates of wages have not been prescribed. But the State Governments are employed to do it. They can bring about changes in the Minimum Wages Act so as to be applicable to them The position is that the State Governments are empowered to add any employment to the schedule to the Act. They can, therefore, amend and apply the Minimum Wages Act wherever they like and even so in the film industry.

श्री वसंत साठे : इडस्ट्री की डेफिनिशन मे पहले आना चाहिए। वह एक दफा उसमें आ गया तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करना आसान हो जायगा। लेकिन शुरूआत तो हमें करनी पड़ेगी।

SHRI BALGOVIND VERMA : I agree that special legislation for the workers in this industry is necessary. Shri Viswanathan mentioned that there were no holidays for the workers and that they had to work throughout the year, that no regular work was given to them and they were at the mercy of the employers. All these things are correct. But it is not correct to say that none of the labour laws are applicable to them. Some labour laws are applicable to one or more of the three sectors of the industry covering production, distribution and exhibition: Factories Act 1948, Payment of wages Act 1936, Workmen's Compensation Act 1923, Industrial Disputes Act 1947, Industrial Employment Standing Orders, 1946, etc. All these Acts apply more or less to the film industry.

SHRI VASANT SATHE : To those who come within the definition of 'worker'.

SHRI BALGOVIND VERMA : The application of some of the above labour laws to the film industry is however beset with difficulties. Junior artists and technicians employed in the production centre of the industry may not come within the purview of the definition of the workmen under the Industrial Disputes Act of 1947. We have taken note of it. It is not that we are not looking into it. Section 17 (3) of the Factories Act 1948 provides that effective provision should be made for prevention of glare either directly or indirectly from a source of light. I think Prof. Mukherjee referred to this point and said that such glare was not good to the workers and it was detrimental to their health. We have taken note of it. This section does not meet with the requirements of the production sector where brilliant lights are required for shooting. Similarly, the provisions of sections 66 and 67 of the Factories Act prohibiting employment of women and children between certain hours or the employment of children below the age of 14 cannot be enforced in the production sector of the film industry. We feel that there are some defects in the labour laws which do not apply there and we are going to correct this in the Bill which we shall be bringing forward before this House very soon. The enforcement of the Shops and Commercial Establishments Act and Workmen's Compensation Act in the film industry also leaves room for improvement. The difficulties of workers employed in the production sector have been accentuated by the fact that producers depend heavily on borrowed capital at high rates of interest and pay a few top artists fabulous sums leaving little for the majority of other categories of workers. Shri Pandey referred to this point. This has also been taken note of. Maximum share is taken by the top artists and the standbys and part-time workers are ill paid.

Arising out of the existing ineffective application of labour laws in the film industry the question of initiating special legislation for regulating the working conditions and wages in the film industry has been under the exhibition of the Government for the last several years in consultation with the State Governments concerned and the Ministry of Information and Broadcasting.

Mr. Sanghi dealt at length with all these aspects. We are alive to our duties. We do not want to bring in piecemeal legislation. We want to bring a comprehensive legislation so that all aspects may be fully covered.

17.00 hrs.

SHRI N. K. SANGHI : But it has taken more than three years.

SHRI BALGOVIND VERMA : Government is looking into it very keenly. We do not want any lacunae to be left. I will explain the reasons for the delay.

A draft outline of the proposed legislation was prepared and circulated for comments in October 1965 to State Governments and the Central Ministries concerned and 55 organisations of employers and workers in the film industry. The proposal for enacting legislation was placed before the Standing Labour Committee held in February, 1966. The committee recommended that a Tripartite Sub-Committee should be set up to consider the draft scheme and make suitable recommendations. A Tripartite Sub-Committee was therefore, set up in November, 1966, under a senior officer of the Ministry. It consisted of 14 members of which 4 members represented the workers' organisations and an equal number of members represented employers' organisations. The remaining members represented the Central and State Governments The sub-committee submitted its report in September, 1968 and it was placed before the 29th session of the Standing Labour Committee held in New Delhi on the 23rd and 24th July, 1970 The committee approved the draft outline of the scheme of legislation recommended by the sub-committee.

The views of the sub-committee are :

(1) Even though the workers in the film industry are protected under the existing labour laws, there is need for a special legislation for the industry. The proposed legislation should set out only the fresh provisions while for the remainting, it should indicate the provisions in the existing labour laws which should apply. The legislation should be brought forward by the Central Government but the rule-making power should vest in the State Governments.

(2) The proposed legislation should cover all the three sectors of industry, viz., production, distribution and exhibition.

(3) The definition of the term "employer" should be wide enough to cover producers who engage free-lance artistes and technicians on contract basis.

(4) The definition of the term "Worker" which should specifically include free-lance artistes, script writers and dancers, should be exhaustive and the limit of monthly emoluments should be Rs. 1,000.

(5) The term "wages" should be defined as in the Payment of Wages Act.

(6) There should be provision for registration of establishments, employers and licences shonld be issued only if the minimum conditions regarding deposit and availability of completed script are fulfilled.

(7) The term "establishment" should be defined in the proposed legislation.

(8) Working hours should be fixed separately for different classes of employees depending on the requirements in each case.

(9) There should be provision for facilities for workers regularly employed but not for free-lance and purely casual workers. Casual workers shonld be given some monetary compensation in lieu of leave.

(10) The State Governments should have powers to make rules laying down the circumstances in which workers, including women and children, could be employed in the production of cinamatographic films between 7 P M. to 8 A. M.

(11) The State Governments should have powers to lay down standards for controlling glare or formation of shadows in the production of cinematographic films.

(12) There should be provision for rest rooms in film studios.

(13) Gratuity should be payable to regular employees and not to temporary, casual and free lance workers. The scale of gratuity should be on the lines laid down in the Working Journalists Act.

(14) In the matter of retrenchment, the provisions of the Industrial Disputes Act should be applied.

(15) As regards penalty, the maximum fine should be Rs. 2,000. Fines at enhanced rates should be levied for repeated and continuous offence, on the lines of the provisions of the Factories Act.

The report of the Sub-Committee was circulated to the State Governments and Union Territories and the concerned organisations of employers and workers for comments. On the

basis of the comments received, a scheme of legislation is being examined in consultation with the Ministry of Information and Broadcasting. Therefore, no useful purpose will be served by the Bill of Shri Samanta.

Apart from this consideration, there are certain lacunae in the present Bill. These are:

(1) Some important terms, e. g. "employer", "establishment", "wages" etc., have not been defined in the Bill.

(2) There is no provision in the Bill for the registration of producers' establishments—a very important control mechanism for an industry of this kind.

(3) The Bill does not contain any provision for giving powers to States to make rules for laying down the circumstances in which workers, including women and children could be employed in production of films at night, or for laying down standards for controlling glare or for formation of shadows.

(4) Clause 7 of the Bill provides for constitution of a Wage Board for the film industry. Some of the State Governments have already added employment in the film industry in Schedule I to the Minimum Wages Act and have also fixed minimum wages.

(5) Clause 11 of the Bill provides for the levy and collection of a few on the earnings of workers and emplovers for the purpose of promoting the welfare of workers who have either retired or are unemployed or in indigent circumstances. This fee is in the nature of a tax. Because of the nature of their employment, a large number of workers would not be benefited by the provisions of the Bill. Further, the utilisation of the fund is left to a purely official machinery which is not desirable.

(6) Clause 15 of the Bill provides for working hours. This clause does not take cognizance of the fact that different limits for working hours will have to be prescribed for different categories of workers.

(7) Clauses 5 and 17 of the Bill provide for gratuity and leave. There is no provision stipulating that these benefits should not be available to free lance and purely casual workers.

For these reasons, I oppose the Bill as also all the motions or amendments thereto.

I assure the hon. Members that we are contemplating bringing forward an exhaustive Bill in this august House very soon. Therefore, I would request the mover of the Bill to kindly withdraw it.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): The recommendation was made in 1969 to have a comprehensive Bill and after 2½ or 3 years a draft legislation was prepared. After 2½ years it is found that there are so many lacunae in the legislation Who are the persons responsible for this draft legislation?

MR CHAIRMAN: The hon. Minister has dealt with the matter as best as he could. If the hon. Member is not satisfied with his reply, I am afraid there is no occasion for the hon. Member to ask questions at this stage.

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : सभापति जी, श्री सामन्त की ओर से मैने इस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित किया था । इस विधेयक का सबसे बड़ा उद्देश्य सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना था कि मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम चलचित्र है और इसलिये हम उसके ग्लैमर और इस उद्योग में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ से—जैसाकि आपने ठीक ही कहा, हम अपनी आंखे बन्द नही रख सकते है । कहा से उद्योग आरम्भ होता है और कहां समाप्त होता है इस प्रक्रिया में किन किन परिस्थितियो मे समाज, कार्यकर्ता, देश, संस्कृति, विचार, चरित्र कैसे कैसे समाज में ये सब व्यथायें पैदा होती है, इन पर भी हमें ध्यान देना होगा । मनोरंजन का सबसे बड़ा महत्व है और इस मनोरंजन के माध्यम में, चलचित्र के माध्यम से रूप और सौन्दर्य का बड़ा प्राधान्य है, और इस रूप और सौन्दर्य को जिस प्रकार हमने अपनी तमाम परम्परागत संस्कृति को बालाये ताक रख कर के बाजार में नीलाम किया है पैसे के नाम पर, बोक्स हिट करे इस नाम पर, यह हमारे लिये खेद की बात है । हुस्न के बारे में यह तसव्वुर किया गया है, जरा सुनिये :

हुस्न तो हगामे बाजार में मसरूफ़ रहा,
और इश्क तो चुप है
सजाये हुए महफिल तनहा ।

[श्री राम सहाय पांडे]

जहां डिवोशन है, जहां प्यार है, वहां उस हंगामें सौन्दर्य की बात नहीं है। सौन्दर्य का यदि प्राधान्य न होता तो हर प्रोड्यूसर ब्लैक से पैसा लेकर इनवेस्ट न करता, जो कि अभी मुल्तानियों से पैसा लेकर 100 रु० के 40 रु० ब्याज का देकर ऐसी पिक्चर बनाते हैं। क्योंकि वह देखते हैं कि इस देश में सैक्स स्टारवेशन है, सौन्दर्य की बड़ी भारी पिपासा हैं, कला के नाम पर वह ऐसे चित्र को प्रस्तुत करते है कि यदि नायिका के, हीरोइन के वस्त्र उघाड़ कर उसके अंगों को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं तो एक जलाशय में, एक स्विमिंग पूल में और उसके परिधानों को ट्रांसपेरेन्ट करके उसके शरीर को दिखाना चाहते हैं, और इस प्रकार पैसा पैदा करना चाहते हैं। सौन्दर्य का जिस प्रकार परवर्टेड, नग्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, आज इन नग्नता से सारा यूरप थक चुका है। और समाज को नग्न करने के बाद कहां है वह संस्कृति और कहां है वह आकर्षण ? सौन्दर्य की पूजा भी अगर करनी होगी तो परिधान के अन्दर करनी होगी, वस्त्रों के अन्दर करनी होगी। लेकिन सौन्दर्य के ऊपर से वसन जहां उतार दिये गये हैं, जहां नग्नता आ चुकी है, आज वहां उद्योग डगमगा रहा है, और यहां हम इस संस्कृति को, उस धरोहर को, उस थाथी को नहीं जाने देना चाहते।

हम सौन्दर्य के प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार इस देश की मन:स्थिति को समझ कर, कैसा चित्र बनाने से, किस प्रकार का रूप देने से, किस प्रकार का उसके प्रदर्शन से हमें कैसे अधिक पैसा प्राप्त हो, वह जो मोटिवेशन है, यह कल्पना है, मैं इसकी निन्दा करता हूं। और इसलिये श्रीमन, आप पीठाधीश हैं इस समय, आप जब यहां बैठे हुए थे तब एक सदस्य थे, लेकिन अब आप सदन के कस्टोडियन हैं, आप ने ठीक कहा कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मैं इसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि यदि चल-चित्र उद्योग एक बात निष्ठा के साथ तय कर ले कि इस राष्ट्र का चरित्र निर्माण करना है, चरित्र के निर्माण करने का मैं सैक्स से बोध नहीं जोड़ता हूं, कार्य करने के प्रति गरिमा का भाव पैदा करना है, इस देश को उठाना हैं, परस्पर सम्बन्धों को जोड़ना है, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति दायित्व को समझे इसका बोध कराना है, इससे ज्यादा उसके लिये और कोई माध्यम नहीं हो सकता।

मैंने एक चित्र देखा था, एक जापान का चित्र था जो मौन था, उसमें श्रम की गरिमा और प्रतिष्ठा का इतना श्रेष्ठ बोध था कि एक नायक नीचे से पानी लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है, उसकी पत्नी नीचे से पानी ले करके पहाड़ पर एक खेत को सींचती थी, छोटे से खेत को सींचती है, छोटे बच्चे पौधे की तरह उगते हैं, उसमें से एक का देहान्त हो गया। बच्चा जिस पाठशाला में पढ़ता था उस पाठशाला के सारे विद्यार्थी संवेदना प्रकट करने के लिये आये उस समय मां बड़े दु:ख से रो पड़ी तो उसका पिता इंगित करता है कि यह बच्चा तुम्हारा मर तो जरूर गया है, लेकिन कर्तव्य तुम्हारा क्या है ? यह एक पौदा उग रहा है। एक बार मां विचलित हुई, उस पौदे की तरफ देखा, अपने कर्तव्य की तरफ देखा और फिर बाल्टी उठाई और पानी से सिंचाई आरम्भ कर दिया। नीचे से पानी लाना, उसको गति, पौदों की रक्षा जीवन का वह एक क्षण था जिसमें दुखी होने के बाद भी उस दु:ख से अपने आपको अविचलित बना कर वह कर्तव्य से कहीं पर भी डिगी नहीं। इसमें कहां रोमांस है, कहां सौन्दर्य है ? लेकिन हैं एक रोमांस और एक सौन्दर्य। वह सौन्दर्य है मानवता के अन्दर की अनुभूति, मानवता के अन्दर छिपी हुई प्रतिभा, कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति तथा उद्देश्य का दर्शन। कौन दर्शक होगा जिसकी आंखों से उस समय दो आंसू गालों पर न ढुलक गये हों। ऐसा एक विचार, समाज की एक अनुभूति उसने प्रदर्शित की। कर्तव्य एक तरफ, परिवार में एक बच्चे का मरण एक तरफ, फिर कर्तव्य पर रत होना एक तरफ, कितनी अच्छी बात थी।

आज बड़े प्रोड्यूसर, बड़े कलाकार सौन्दर्य को लेकर बाजार में बैठते हैं और पैसा लेते हैं 25—30 करोड़ रु० नकद । 25 हजार सिनेमा विंडोज में खनकता हुआ पैसा आता है । उसको देने वाले कौन लोग है ? थके हुए लोग, जिन के लिए और कोई मनोरंजन नहीं । मनोरंजन का पंच-द्रव्य आज सिनेमा बन गया है, इसलिये कि वह थके होते है, मनोरंजन चाहते हैं । वह निकट के सिनेमा से चले जाते है । पैसा नही होता है तब भी जाते है, उधार लेकर जाते है । अगर आज हाउसहोल्ड एक्स्पेन्सेज मे सिनेमा के एक्स्पेन्सेज को जोड़ लिया जाय तो कौन सा ऐसा परिवार है जिसके सदस्य चल-चित्र नहीं देखते है, जो नये बन कर आते है ।

जितने सुन्दर चित्र होंगे उतना अच्छा समाज बनेगा । जितने गन्दे, बुरे, भद्दे, अश्लील चित्र होंगे वैसी ही गिरी हुई हमारी भावनायें होंगी । मै बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं हूं, बिल्कुल पोंगापन्थी व्यक्ति नही हूं, मै चाहता हू कि सौन्दर्य का विकास हो, मैं चाहता हूं कि कला का विकास हो, मै चाहता हूं कि आधुनिकता से उसको दूर न रक्खा जाये, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते समय, कहानी का चयन करते समय हीरो और हीरोइन का चयन करते समय इस बात का ध्यान रक्खे कि बाक्स कौन सी चीज हिट करती है, कैसे चल-चित्र दस, बारह और बीस हफ्ते चलेगा और कैसे हम लोगों का शोषण करेंगे । फिर इस सबका लाभ अगर नीचे तक आता हो, उसका आर्थिक प्रवाह, आर्थिक लाभ की गंगा का प्रवाह अगर नीचे तक जाता हो, जो लोग बारह-बारह, चौदह चौदह घंटे हाई वोल्टेज में काम करते हैं, अगर, वह उन तक पहुंचता हो या उनका फायदा होता हो तो ठीक है । मुझे मालूम है जिनका सिनेमाओं से संबंध है, सैकड़ों नहीं हजारों महत्वा-कांक्षायें लेकर कलाकार बनने की प्रवृत्ति से के स्वप्न लेकर आते हैं, देश भर से तरुण बहनें और बेटियां, तरुणी बालाएं उसी परिकल्पना के साथ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आदि शहरों की तरफ जाती है । वह लोग जिन एजेंसियों के चक्कर में पड़ती है और जिस प्रकार उनका शरीर से, मन से, बुद्धि से और पैसे से शोषण होता है उसको इस सदन में बहुत खोल कर रखने में भी लज्जा आती है ।

आप एक्स्ट्राज की बात लीजिये । प्रोड्यूसर कहता है कि फोक डान्स दिखलाना है और उसके लिए पच्चीस सुन्दर मुखाकृतियों की लड़कियां चाहिए । शाम तक पच्चीस लड़कियां आ जाती हैं । उनकी क्या सिक्योरिटी है । मैं श्री सांघी से पूछता हूं, वह सब कुछ जानते हैं, शायद फेडरेशन के अध्यक्ष भी है । उन पच्चीस सुन्दर मुखाकृति वाली तरुणी बालाओं द्वारा होने वाले संगीत और नृत्य का संयोजन करने वाली जो एजेन्सी है वह उनको लेती है, और पांच दस वर्ष बाद जब उनका यौवन समाप्त हो जाता है तब उनकी क्या हालत होती है, यह श्री डागा जानते हैं और सभापति महोदय, आप भी जानते हैं । जब उनकी तरुणाई कला से मंडित हो जाती है, जब उनके नृत्य से आनन्द आता है और पिक्चर सुन्दर बनती है तो उसके बाद यह कंट्रेक्ट भी होनी चाहिए कि उनको इतना भरपेट पैसा मिलना चाहिए कि वह अपनी असमत से खेल कर के समाज में अपनी गर्दन लज्जा से न झुका लें । यही कलाकार हैं जिन्होंने अपने नृत्य और संगीत से मनोरंजन प्रदान किया है लेकिन आज उनको ही अपना शरीर बेचना पड़ता है । इसलिये उसके अन्धेरे को, उसके धोखे को, उसके गन्देपन को, उसकी हीनता को, उसके जघन्य स्वरूप को, भ्रष्ट स्वरूप को भी हमें देखना होगा ।

मंत्री महोदय यहां बिल लायें या न लायें, लेकिन इस बिल के माध्यम से जो सदन का ध्यान दिलाया गया है वह सबसे बड़ा काम है । हमारे देश और समाज में मनोरन्जन का जो सबसे बड़ा माध्यम है, उसके प्रति हम कितने उदासीन हैं ? क्या वे महिलायें हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं, जो एक्स्ट्रा बनने के बाद आखिर में प्रास्टीट्यूट बन जाती हैं ? हम ऐसे कितने ही आदरणीय कलाकारों को जानते हैं, जो एक समय उरूज, उन्नति और लोकप्रियता

[श्री राम सहाय पांडे]

के शिखर पर थे, लेकिन जब उनके जीवन का सूर्य अस्त होने को आया, तो उनके भूखो मरने की नौबत आई। आज हमारे कलाकारो के लिये कोई सरक्षण नही है। जब वे बूढ़े हो जाते है, उनका गर्दन झुक जाती है और हाथ पैर काम करना बन्द कर देते है, तो उनकी क्या हालत होती है? इसलिये उनके लिए कुछ न कुछ सरक्षण को व्यवस्था होनी चाहिए।

केवल वही व्यक्ति कलाकार नही हैं, जो दस दस लाख रुपये लेते है। जो लिखते है, सोचते है, अभिनय, नृत्य और सगीत देते हैं, वे भी कलाकार है। इसके अतिरिक्त झाड़ू लगाने वाले, दरबान, सिनेमा के एटेंडेट, साउड रिकार्डर और कैमरामैन आदि भी इस उद्योग के अग है और हमे उन सब को सरक्षण देना चाहिए। हम चल-चित्र उद्योग को ऐसे सुन्दर और स्वस्थ रूप म प्रस्तुत करना चाहते है, जहा कोई गन्दापन न हो, भ्रष्ट आचरण न हो, ब्लैक के पैसो का विपुल प्रवाह न हो।

इस देश मे कुछ कलाकारो को एक एक चित्र के लिए दस दस लाख रुपये दिये जाते है। जो व्यक्ति तीन चार चित्रो मे काम करके तीस लाख रुपये कमा लेगा, वह क्या करेगा? वह इतनी एफ्लुएन्ट लाइफ बनायेगा, जो हमारे जीवन मे हाहाकार पैदा कर देगी।

मै कलाकारो से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ब्लैक के लाखो रुपये रखने की प्रवृत्ति को छोड दे। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति के अनुरूप, इस देश की सामाजिक और सास्कृतिक परम्पराओ के अनुसार सादगी से रहे। कला, सौन्दर्य और रूप उनको भगवान ने दिया है। उनसे हमे यह अपेक्षा है कि वे इस बदलते हुए समाज मे सादगी,गरिमा और सौम्यता के साथ रहे। हम यह भी चाहते है कि निचले कलाकारो का भी उद्भव और उन्नति हो, उनको उचित सरक्षण मिले। ऐसा न हो कि उनका जीवन कुठा और निराशा से भरा रहे।

अन्त मे उन लाखो बुद्धिजीवी कलाकारो की ओर से, जिनके जीवन-यापन से कोई स्थायित्व नही है, जिनके लिये ग्रैचुइटी, प्राविडेट फड और ट्रिब्यूनल आदि की कोई सुविधा नही है, मै मत्री महोदय से बड़े दर्द के साथ निवेदन करना चाहता हू कि वह अपने आश्वासन के अनुसार शीघ्र से शीघ्र बिल लायें, ताकि इन छोटे से छोटे और साधारण से साधारण कलाकारो को कुछ सरक्षण मिल सके। इस बात की आवश्यकता है कि इस असगठित और विश्रृखलित उद्योग के बिखरे हुए धागो को जोडा जाये, उसको नैतिक जीवन दिया जाये, देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दी जाये। हम सब मनोरजन चाहते है, कला की पूजा करना चाहते है। लेकिन यदि कलाकार कला की पूजा करवा कर स्वय भ्रष्ट हो, तो वह कलाकार नही है। कला की पूजा और उपासना होनी चाहिए और यदि कलाकार सादगी, दायित्व और गरिमा के साथ कला के माध्यम से हमारे सामने आता है, तो हम उसके सामने मस्तक झुकायेंगे। जो कलाकार भारतीयता और हमारी सामाजिक तथा सास्कृतिक परम्पराओं का अनुगमन करेगे, वे हमारे प्रिय-पात्र होगे।

मै मत्री महोदय से कहूगा कि वह अपने आश्वासन के अनुसार एक अच्छा बिल जल्दी लायें और सदन के विचारो को ध्यान मे रखते हुए उन लाखो लोगो के साथ न्याय करे।

सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हू, मत्री महोदय को धन्यवाद देता हू और श्री सामन्त को भी, धन्यवाद देता हू कि उन्होंने मुझे इस बिल को पायलट करने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN : There are two amendments moved to this Bill-one by Mr. Daschowdhury and another one by Mr. Subodh Hansda. Are they pressing their amendments ?

SHRI B K. DASCHOWDHURY : Yes, I would like to say a few words only.

MR. CHAIRMAN : Not now. This was discussed thoroughly.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : My amendment is for referring the Bill to the Select Committee because the Government is taking quite a long time.

MR. CHAIRMAN : Do you press that it should be put to the vote of the House ?

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : I press my amendment.

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That the Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry, be referred to a Select Committee consisting of 15 members, namely :—
>
> Shrimati Mukul Banerji, Shri Jyotirmoy Bosu, Shrimati Jyotsna Chanda, Shri H. R. Gokhale, Shri Samar Guha, Shri Indrajit Gupta, Shri Nihar Laskar, Shri V. Mayavan, Shri Shyam Sunder Mohapatra, Shri Priya Ranjan Das Munsi, Shri Ramsahai Pandey, Shri S. C. Samanta, Shri Arjun Sethi, Shri Nawal Kishore Sharma ; and Shri B. K. Daschowdhury.
>
> with instructions to report by the first day of the next session."(1)

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : Mr. Subodh, are you pressing you amendment ?

SHRI SUBODH HANSDA (Midnapore) : In view of the Minister's assurance, I am not pressing my amendment.

MR. CHAIRMAN : Has the Hon'ble Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN : From the concluding remarks, I understand that Mr. Pandey is withdrawing the Bill.

The question is :

> "That leave be granted to withdraw the Bill".

The motion was adopted.

SHRI R. S. PANDEY : Sir, I withdraw the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Seventh Schedule) by Shri S. C. Samanta

MR. CHAIRMAN : Now, we go to the next item.

Mr. Samanta.

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk) : I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

In this Statement of Objects and Reasons I have clearly put why I want education to go to the Concurrent List.

This Bill is being discussed throughout the country, especially the educationists of the country So many Committees and Commissions were formed but the Government could not come to a definite conclusion whether education should be brought to the Concurrent List.

Education is a matter of national concern and should be treated from that point of view. The role of the Government of India in the development of education should be judged in that context. In the Union List, that is, in List I of the Seventh Schedule of the Constitution, Entries 63 to 66 and Entry No. 25 of the Concurrent List enumerate the only subjects relating to Education where the Union Government has the power of legislation and direct control. Barring this limited field, the Government of India has not been vested with any specific responsibility in the matter of education and the vast field of education has been left to the exclusive domain of the States.

The result has been far below our expectation. The radical reconstruction of the educational structure recommended by experts and expert committees including the Education Commission has not been brought about. I know that the Education Commission did not favour the idea of inclusion of education in the Concurrent List. The Commission indeed recommended as follows. I quote :

> "An intensive effort should be made to exploit fully the existing provisions of